

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2021—कार्तिक 7, शक 1943

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 सितम्बर 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, अपर मुख्य सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल लाईन प्रोजेक्ट) तथा अध्यक्ष छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल को केवल अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

2. श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994), प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, वन विभाग, आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-निवेश आयुक्त, सीएसआईडीसी (मुख्यालय नई दिल्ली) को केवल आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार से मुख्य करते हुए प्रमुख आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है। शेष प्रभार यथावत् रहेंगे।
3. डॉ. एम. गीता, भा.प्र.से. (1997), प्रभारी कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थ करता है।
4. श्री अमृत कुमार खलखो, भा.प्र.से. (2002), सचिव, श्रम विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, माननीय राज्यपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
5. श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. (2003), सचिव, माननीय मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, लोक निर्माण विभाग, सचिव, विमानन विभाग एवं सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को केवल सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए सचिव, खनिज साधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है। शेष प्रभार यथावत् रहेंगे।
6. श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003), सचिव, जल संसाधन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, खेल एवं युवा कल्याण, सचिव, संसदीय कार्य विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, पंचायत का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
7. श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004), सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, कौशल विकास एवं संचालक, पंचायत को केवल संचालक, पंचायत के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है। शेष प्रभार यथावत् रहेंगे।
8. श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से. (2004), सचिव, खनिज साधन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
9. श्री धनंजय देवांगन, भा.प्र.से. (2004), सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
10. श्री नीलम नामदेव एक्का, भा.प्र.से. (2005), सचिव, जनशिकायत एवं निवरण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, विमानन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
11. श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही., भा.प्र.से. (2006), श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, छ.ग. प्रशासन अकादमी के पद पर पदस्थ करता है।  
  
श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही., भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, छ.ग. प्रशासन अकादमी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।
12. श्री भूवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006), विशेष सचिव, ग्रामोद्योग विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, भू-अभिलेख एवं संचालक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार) के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
13. श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. (2008), प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

14. श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, भा.प्र.से. (2008), विशेष सचिव, कृषि विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मिशन संचालक, समग्र शिक्षा के पद पर पदस्थ करता है।

श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत मिशन संचालक, समग्र शिक्षा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

15. श्री अभिजीत सिंह, भा.प्र.से. (2012), प्रबंध संचालक, छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, भू-अभिलेख के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, गृह विभाग तथा संचालक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

16. श्री रणबीर शर्मा, भा.प्र.से. (2012), संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, रायपुर के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, कृषि विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री रणबीर शर्मा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

16. श्री सुधाकर खलखो, भा.प्र.से. (2012), संचालक, ग्रामोद्योग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. माटीकला बोर्ड को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

17. श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, वन विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

18. श्री ऋतुराज रघुवंशी, भा.प्र.से. (2014), आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है।

श्री ऋतुराज रघुवंशी, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

19. श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, भा.प्र.से. (2016), अपर संचालक, उच्च शिक्षा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के पद पर पदस्थ करते हुए अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

20. श्रीमती तुलिका प्रजापति, भा.प्र.से. (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर-रामानुजगंज को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

**वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 1-01/2020/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री एस.एस.डी. बड़गैया (1996)	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), कांकेर वृत्त, कांकेर.	मुख्य वन संरक्षक, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर.
2.	श्री राजू आगासिमनी (2006)	क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., नवा रायपुर अटल नगर.	प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), कांकेर वृत्त, कांकेर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आर. के. चंचलानी**, अवर सचिव.

**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 सितम्बर 2021

क्रमांक/11055/01/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	उपनी प.ह.नं. 26	67.445	कार्यपालन अभिर्यता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैरॉज निर्माण संभाग क्र. 1, खरसिया.	साराडीह बैरॉज के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**जितेन्द्र कुमार शुक्ला**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 17 सितम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2020-21.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	घोठला छोटे प.ह.नं. 37	4.233	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्र. 01, खरसिया जिला रायगढ़.	साराडीह बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.**

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 22 सितम्बर 2021

प्र. क्रमांक 03/अ-82/भू-अर्जन/4327/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही  
(ख) तहसील-पेण्ड्रा रोड  
(ग) नगर/ग्राम-गौरखेड़ा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.610 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
276	0.370
278	0.240
<b>योग</b>	<b>0.610</b>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनकछार जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

(1)

(2)

23/1

0.065

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

60/1

0.372

60/5

0.327

87/3

0.040

88/1ग/4

0.239

गौरेला-पेण्डा-मरवाही, दिनांक 22 सितम्बर 2021

99/1ग

0.045

101/3

0.045

19/1

0.049

101/4

0.045

101/9

0.045

9/1

0.121

99/1घ

0.101

96

0.077

23/2

0.032

10/1/द

0.137

प्र. क्रमांक 04/अ-82/भू-अर्जन/4317/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

योग

32

4.735

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गौरेला-पेण्डा-मरवाही
- (ख) तहसील-पेण्डारोड
- (ग) नगर/ग्राम-ठेंगाडांड
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.735 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनकछार जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

खसरा नम्बर

रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1/1ण/1

0.066

1/1/न

0.206

10/3

0.368

17/2

0.364

9/2

0.130

16/1

0.267

10/5

0.012

10/13

0.089

10/14

0.089

10/15

0.089

16/2

0.020

18/2

0.097

19/6

0.178

24

0.223

25

0.069

42

0.481

60/3

0.247

गौरेला-पेण्डा-मरवाही, दिनांक 22 सितम्बर 2021

प्र. क्रमांक 04/अ-82/भू-अर्जन/4348/2021.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गौरेला-पेण्डा-मरवाही
- (ख) तहसील-पेण्डारोड
- (ग) नगर/ग्राम-दौजरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.972 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
		353/1	0.202
		205/3, 205/12, 205/13	0.243
146/3	0.567	137/21	0.190
190/2	0.061	205/15	0.081
146/1	0.101	240/1	0.061
148/3	0.182	205/11	0.190
190/1	0.061	205/9	0.150
		205/8, 360/4	0.040
योग	05	370/5	0.036
		343/31	0.142
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तिपान नदी व्यपवर्तन योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.		342/12	0.049
		343/31	0.061
		459/14,	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.		460/17	0.024
		343/36	0.053
		342/11/घ	0.036
		459/4	-
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 22 सितम्बर 2021		460/7	0.036
		462/3	0.036
		463/4	
प्र. क्रमांक 05/अ-82/भू-अर्जन/4321/2021.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		343/33	0.065
		343/38	0.101
		459/16	0.020
		460/19	0.020
		140/1	0.057
		140/4	0.036
		140/5	-
		343/11/ख	0.024
		342/13	0.129
		342/14	-
		342/16	0.061
(1) भूमि का वर्णन-		342/20	-
(क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही		342/15	0.045
(ख) तहसील-पेण्ड्रा-रोड		342/22	0.036
(ग) नगर/ग्राम-बढ़ावनडांड		343/23	-
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.261 हेक्टेयर		343/30	0.073
		342/11/ग	0.069
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	459/3	-
(1)	(2)	460/4	-
		462/2	-
		459/8	0.024
193/1, 194/1	0.312	460/11	-
358/1	0.101	459/12	0.020
355/1	0.024	460/15	-
330/1न	0.089	343/12	0.024
205/10	0.306	407	0.085
205/7	0.061	343/31/ख	0.061

(1)	(2)	(1)	(2)
418	0.077	483/1	0.040
399/1	0.065		
410	0.101	योग	96
406/1	0.113		6.261
61/5	0.020	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनकछार जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.	
139/2	0.073		
142	0.162		
193/2, 194/2	0.113	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.	
140/2	0.036		
343/32	0.036		
139/5	0.134		
483/2	0.016		
342/26	0.077		
444/1	0.085	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 22 सितम्बर 2021	
340/2/ख	0.040		
399/2	0.036	प्र. क्रमांक 06/अ-82/भू-अर्जन/4325/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	
409/2	0.069		
409/1/क	0.093		
472/3	0.032		
471/3	0.028		
472/1	0.032		
419/1	0.036		
413	0.024		
419/2	0.024		
342/4	0.101		
342/7	0.024		
444/2	0.016		
470	0.061		
141/2	0.073		
195/2, 195/3, 195/5	0.073		
195/1	0.089		
340/6	0.053		
140/3	0.040		
340/2/ग	0.049		
417	0.020		
471/2	0.024		
403/1	0.057		
139	0.032		
342/1	0.093		
459	0.012		
460	0.020		
141/1	0.061		
340/2क	0.081		
500	0.081		
21/20	0.081		
352/3	0.069		
352/2	0.020		
		खसरा नम्बर	रकबा
			(हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
		40	0.162
		21/6/क	0.045
		21/6/ख	0.170
		21/4	0.081
		10	0.113
		36/3	2.023
		42/1	0.093
		30/3	0.130
		योग	8
			2.808



(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटरियाडांड  
व्यपवर्तन योजना के शीर्ष/नहर निर्माण कार्य हेतु.

(1)

(2)

98/1

0.202

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी  
(रा.), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

योग

16

2.862

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तिपान नदी  
व्यपवर्तन योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी  
(रा.), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 22 सितम्बर 2021

प्र. क्रमांक 06/अ-82/2016-17/भू-अर्जन/4329/2021.—  
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई  
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में  
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि  
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता  
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम,  
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित  
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता  
है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
- (ख) तहसील-पेण्डारोड
- (ग) नगर/ग्राम-हराटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.862 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15	0.445
96/2	0.162
12/3	0.069
13	0.162
14	0.291
12/2	0.024
11/2	0.101
17/4	0.073
11/1	0.401
1/2	0.065
2/3	0.089
9	0.081
11/3	0.389
94/2	0.162
96/1	0.146

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 22 सितम्बर 2021

प्र. क्रमांक 09/अ-82/2016-17/भू-अर्जन/4349/2021.—  
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई  
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में  
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि  
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता  
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम,  
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित  
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता  
है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
- (ख) तहसील-पेण्डारोड
- (ग) नगर/ग्राम-सधवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.701 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
931	0.073
933/2	0.065
934	0.085
908	0.057
872/2	0.008
873	0.036
907/2	0.069
853/2	0.121
854	0.061
855/2	0.101
933/1	0.295

(1)	(2)	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 22 सितम्बर 2021	
935/1ग	0.466	प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2017-18/भू-अर्जन/4331/2021.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	
870/1	0.073		
915	0.077		
745/2	0.024		
746	0.032		
748/1	0.093		
826/3	0.069		
909/4	0.101		
857	0.142		
855/11	0.020	अनुसूची	
869/3	0.073	(1) भूमि का वर्णन—	
853/1	0.061	(क) जिला-गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	
914	0.178	(ख) तहसील-पेण्ड्रा रोड	
101/2क 2ख 2ग 2घ	0.466	(ग) नगर/ग्राम-पीपरखूटी	
916/1	0.004	(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.247 हेक्टेयर	
1206	0.016	खसरा नम्बर	रकबा
906/1ङ	0.283		(हेक्टेयर में)
869/4	0.036	(1)	(2)
856/3	0.012		
	0.085		
826/2	0.081	1268 P से	0.809
828/1	0.445	1268 P से	0.352
871/1	0.069	1268 P से	0.150
906/1झ	0.279	1268 P से	1.558
913/1	0.271	1268 P से	0.384
907/1	0.162	1268 P से	0.263
932	0.008	1268 P से	1.619
1205	0.113	1268 P से	0.522
868	0.020	1268 P से	1.619
869/2	0.194	1268 P से	0.971
913/2	0.210		
(933/3, 935/3)	0.284		
1207	0.283		
योग	43	योग	10
	5.701		8.247

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनकछार जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पेण्ड्रा रोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनकछार जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पेण्ड्रा रोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 22 सितम्बर 2021		(1)	(2)
प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2015-16/भू-अर्जन/4319/2021.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		190/1	0.101
		542	0.154
		544/1	0.045
		543	0.024
		191/1	0.194
		191/6	0.024
		194	0.190
		677/4	0.121
		682/4	0.162
		777	0.194
		753/2	0.089
		266/5	0.024
		499	0.065
		498/1	0.081
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन-			
(क) जिला-गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही		266/6	0.032
(ख) तहसील-पेण्ड्रा रोड		191/10	0.049
(ग) नगर/ग्राम-कोटखर्वा		513/4	0.024
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.891 हेक्टेयर		179/1	0.085
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	190/2	0.150
		563/2	0.008
(1)	(2)	174/3	0.020
		683/3	0.113
		782/2	0.142
497/3	0.109	191/5	0.045
500	0.073	191/8	0.040
497/2	0.081	153/1	0.101
715/2	0.405	501/3	0.081
174/1	0.093	503	0.073
193/1	0.190	168	0.073
255/2/2	0.089	170/2	0.040
513/3	0.024	188/2	0.061
154	0.097	169	0.101
253/2	0.089	513/1	0.057
257/1	0.146	781/1	0.065
266/1	0.093	153/2	0.089
191/4	0.049	752/2	0.141
191/9	0.073	572	0.040
257/2	0.113	717/1	0.223
191/2	0.077	563/1	0.016
253/1	0.134	567	0.129
684/2ज	0.186	256/1	0.113
675/2	0.121	255/2/1	0.089
677/6	0.182	752/3	0.101
178	0.101	753/1	0.125
167	0.129	571	0.036
513/2	0.053	782/4	0.020
781/2	0.069	784/2ग	0.024
254	0.117		

(1)	(2)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
योग	73	731/6क/32	0.324
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तिपान नदी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.	0.024	759	0.081
		760	0.077
		742	0.178
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.		743	2.335
		741	0.275
		744/1ग	0.202
गौरेला-पेण्डा-मरवाही, दिनांक 22 सितम्बर 2021		744/2	0.405
		731/6क/8	0.202
प्रकरण क्रमांक 40/अ-82/2019-20/भू-अर्जन/4323/ 2021.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		731/1क/22	0.445
		731/6प/16	0.040
		744/1ख/1	0.202
		731/6क/5	0.866
		758/1	0.607
		योग	14
			6.417
अनुसूची		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आंदुल जोगीडोंगरी जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.	
(1) भूमि का वर्णन-		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.	
(क) जिला-गौरेला-पेण्डा-मरवाही		छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नम्रता गांधी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	
(ख) तहसील-पेण्डारोड			
(ग) नगर/ग्राम-सारबहरा			
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.417 हेक्टेयर			

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़  
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2021

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-21/1885.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने में असफल रहे, श्री रूपधर पुड़ो एवं श्री नेहरू राम कोमरा, जिला-कांकेर को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/79/2018, दिनांक 02 जुलाई, 2021 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

( के. सी. देवसेनापति )  
अति. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

## भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 2 जुलाई, 2021—11 आषाढ़, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/79/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है.

और यतः, 79-अन्तागढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रूपधर पुडो, जो छत्तीसगढ़ के 79-अन्तागढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रूपधर पुडो को कारण बताओ नोटिस दिनांक 4 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 4 मार्च, 2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रूपधर पुडो को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री रूपधर पुडो द्वारा 19 मार्च, 2020 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अपने दिनांक 8 जुलाई, 2020 के पत्र सं. सा.निर्वा./निर्वा.व्यय लेखा/2020/272 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अपने दिनांक 8 जुलाई, 2020 के पत्र सं. सा.निर्वा./निर्वा.व्यय लेखा/2020/272 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रूपधर पुडो ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रूपधर पुडो निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहिंत घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिंत होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 79-अन्तागढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले अंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया अभ्यर्थी श्री रूपधर पुडो, ग्राम-दरगढ़, पो.आ.-साधुमिचगांव, तहसील-दुगूकोंदल, जिला-उत्तर बस्तर कांकिर छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है.

आदेश से,

हस्ता./-

( नरेन्द्र ना. बुटोलिया )

वरिष्ठ प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 2nd July, 2021—11 Asadha, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/79/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 79-Antagarh (ST) Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Uttar Bastar Kanker District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Rupdhar Pudo, Ambedkarite Party of India contesting candidate from 79-Antagarh (ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Uttar Bastar Kanker District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 4th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Rupdhar Pudo, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 4th March, 2020 Sh. Rupdhar Pudo, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Rupdhar Pudo on 19th March, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Uttar Bastar Kanker vide his letter No. SA.Ele/Exp. 2020/Exp. 2020/272 dated 8th July, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Uttar Bastar Kanker vide his letter No. SA.Ele./Ele.Exp. 2020/Exp./2020/272 dated 8th July, 2020, has stated that Sh. Rupdhar Pudo, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Rupdhar Pudo, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Rupdhar Pudo, resident of Village-Dargarh, Post-Sadhumichgaon Block-Durgukondal, Tahsil-Durgukondal, District Uttar Bastar Kanker, Chhattisgarh and the contesting Ambedkarite Party of India candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 79-Antagarh (ST) Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-  
(NARENDRA N. BUTOLIA)  
Senior Principal Secretary,  
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 2 जुलाई, 2021—11 आषाढ़, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/79/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 79-अन्तागढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री नेहरू राम कोमरा, जो छत्तीसगढ़ के 79-अन्तागढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री नेहरू राम कोमरा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 4 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 4 मार्च, 2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री नेहरू राम कोमरा को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री नेहरू राम कोमरा द्वारा 19 मार्च, 2020 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अपने दिनांक 8 जुलाई, 2020 के पत्र सं. सा.निर्वा./निर्वा.व्यय लेखा/2020/272 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अपने दिनांक 8 जुलाई, 2020 के पत्र सं. सा.निर्वा./निर्वा.व्यय लेखा/2020/272 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री नेहरू राम कोमरा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नेहरू राम कोमरा निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 79-अन्तागढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री नेहरू राम कोमरा, ग्राम-तुराखर, पो.आ.-सिदेसर, ब्लाक-तहसील-उत्तर बस्तर कांकेर, तुराखर, छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./—

( नरेन्द्र ना. बुटोलिया )

वरिष्ठ प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.



## ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 2nd July, 2021—11 Asadha, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/79/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 79-Antagarh (ST) Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Uttar Bastar Kanker District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Nehru Ram Komra, Independent contesting candidate from 79-Antagarh (ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Uttar Bastar Kanker District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 4th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Nehru Ram Komra, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 4th March, 2020 Sh. Nehru Ram Komra, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Nehru Ram Komra on 19th March, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Uttar Bastar Kanker vide his letter No. SA.Ele./Ele.Exp. 2020/Exp. 2020/272 dated 8th July, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Uttar Bastar Kanker vide his letter No. SA.Ele./Ele.Exp. 2020/Exp./2020/272 dated 8th July, 2020, has stated that Sh. Nehru Ram Komra has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Nehru Ram Komra, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Nehru Ram Komra, resident of Village-Turakhar, Post-Sidesar, Block-District Uttar Bastar Kanker, Chhattisgarh and the contesting Independent candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 79-Antagarh (ST) Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-  
(NARENDRA N. BUTOLIA)  
Senior Principal Secretary,  
Election Commission of India.

### कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 13 सितम्बर 2021

क्रमांक/11321/वित्त-1/2021.—प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कोरबा जिला में पदस्थ निम्नांकित संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर को आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान में पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना कार्यालय	नवीन पदस्थापना कार्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अरुण कुमार खलखो, डिप्टी कलेक्टर.	जिला कार्यालय कोरबा	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पोड़ी उपरोड़ा
2.	श्री संजय कुमार मरकाम, डिप्टी कलेक्टर.	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पोड़ी उपरोड़ा.	जिला कार्यालय कोरबा

श्री अरुण कुमार खलखो, डिप्टी कलेक्टर को जिला कार्यालय कोरबा में सौंपे गये कार्यों का निर्वहन श्री संजय कुमार मरकाम, डिप्टी कलेक्टर कोरबा द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त किया जावेगा.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

हस्ता./-  
कलेक्टर.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 6th August 2021

No. 648/Confdl./2021/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Suman Dhruv, the then Civil Judge Class-II, Chhuikhadan, District-Rajnandgaon presently posted as Secretary, District Legal Services Authority, Balod, she is hereby, permitted to change her name as “Smt. Suman Singh” in place of “Ku. Suman Dhruv” and to incorporate the name of her husband Shri Rishikeshwar Raj Singh in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

Bilaspur, the 6th August 2021

No. 650/Confdl./2021/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Jasvinder Kaur Ajmani, the then II Civil Judge Class-II, Kharsia, District-Raigarh presently posted as Secretary, District Legal Services Authority, Bemetara, she is hereby, permitted to change her name as “Smt. Jasvinder Kaur Ajmani Malik” in place of “Ku. Jasvinder Kaur Ajmani” and to incorporate the name of her husband Shri Taranbir Singh Malik in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

Bilaspur, the 9th August 2021

No. 654/Confdl./2021/II-2-1/2021.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and ;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Pankaj Sharma, Additional Registrar (D. E. & E.), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	Additional Judge to the Court of Additional District and Sessions Judge.

Bilaspur, the 9th August 2021

No. 656/Confdl./2021/II-2-90/2001 (Part-III)/I-8-6/2001 (Part-III).—(A) Shri Davender Kumar, Member of Higher Judicial Services and Presently posted as Secretary, High Court Legal Services Committee, Bilaspur is now appointed as Additional Registrar (D. E. & E.) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

(B) Shri Prasahant Parashar, Member of Higher Judicial Service and presently posted as V Additional District and Sessions Judge, Raipur is transferred and appointed as Secretary, High Court Legal Services Committee, Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

By order of the High Court,  
DEEPAK KUMAR TIWARI, Registrar General.

---